ईरान-अमेरिका के बीच हुई बातचीत

मस्कट, 06 फरवरी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि शुक्रवार को कई दौर की बैठकों के बाद अमेरिका के साथ बातचीत की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की प्रगति दोनों देशों की राजधानियों में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगी.

श्री अराघची ने बताया शुक्रवार कई दौर की बैठकें हुई। हमारे विचार और चिंताएं बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में साझा की गईं. कुल मिलाकर, यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसकी निरंतरता राजधानियों में होने वाले विचार-विमर्श पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा, अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ आठ

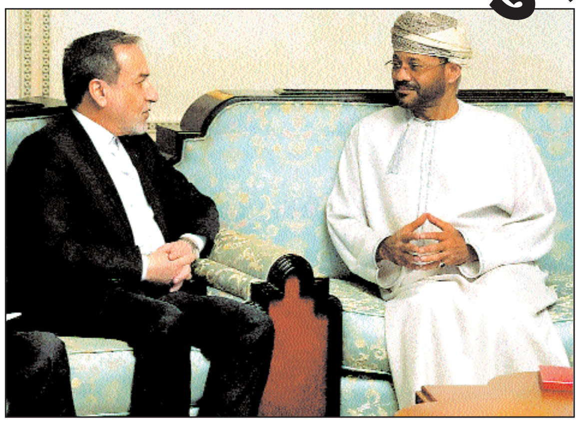

अशांत महीनों के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई है. श्री अराघची के अनुसार, पिछले साल के संघर्ष के बाद व्याप्त अविश्वास एक बड़ी बाधा बना हुआ है. उन्होंने कहा, 12 दिनों के युद्ध के बाद जो अविश्वास पैदा हुआ, वह बातचीत के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है. श्री अराघची ने जोर देकर कहा, हमें सबसे पहले इस अविश्वास को दूर करना होगा और बातचीत के लिए एक ढांचा तय करना होगा.

अमेरिका ने अपने लोगों को ईरान छोड़ने का आदेश

वॉशिंगटन. अमेरिका ने ईरान में में रह रहे अपने नागरिकों को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर चेतावनी जारी की है उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी है. ईरान में वर्चुअल यूएस एम्बेसी की ओर से जारी परामर्श में कहा कि अमेरिकी नागरिक ईरान से प्रस्थान की योजना बनाएं जो अमेरिकी सरकार की सहायता पर निर्भर न हो, क्योंकि सुरक्षा जोखिम, अशांति और यात्रा बाधित होने की आशंका बढ़ गई है. यह चेतावनी ओमान में शुक्रवार को अमेरिका-ईरान वार्ता से ठीक पहले जारी की गई है.

ईडी का अरुणाचल में कई जगहों पर छापा

ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाले का मामला

नई दिल्ली, 06 फरवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाले के सिलसिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है.

यह मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन और वितरण में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और निजी लाभार्थी शामिल हैं. आरोप है कि इन गड़बड़ियों से अपराध की कमाई हुई और उसका अवैध तरीके से धन शोधन किया गया. यह परियोजना 157.70 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती है और इसे प्रशासनिक रूप से तीन सेक्टरों में

बांटा था, जिसमें याचुली (0.00-43.635 किमी), जिरो (43.635-63.700 किमी) और रागा (63.700-149.440 किमी) शामिल हैं. जांच के दौरान पाया कि जिरो के तत्कालीन उपायुक्त ने शुरू में पूरे पोटिन-बोपी हिस्से के लिए 289.40 करोड़ रुपये का मुआवजा अनुमान तैयार किया था. हालांकि, राज्य-स्तरीय बैठक के दौरान मुआवजा पैकेज को रोक दिया गया और फिर उसे 198.56 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया.

जांच से पता चला है कि अधिकारियों ने जानबूझकर ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग (पोटिन-बोपी) परियोजना के याज़ाली सेक्टर में संरचनाओं के बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी मूल्यांकन तैयार करके और प्रमाणित किया तथा अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया. आरोप है कि उन्होंने गैर-मौजूद संरचनाओं और अयोग्य लाभार्थियों को इसमें शामिल करने में मदद की. मौजूदा जांच के हिस्से के रूप में, छह आवासीय परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त, मूल्यांकन अधिकारियों और प्रमुख निजी लाभार्थियों तथा बिचौलियों के परिसर शामिल हैं.

सोते समय घर मे लगी आग से वृद्ध महिला जिंदा जली, पति झुलसा

पन्ना, 06 फरवरी. जिले के गुनौर थाना के समीपी गांव पड़ेरी में बीती रात एक हृदयविदारक हादसा हो गया. खेत में बने कच्चे घर में अचानक आग लगने से 75 वर्षीय वृद्ध महिला श्याम बाई की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि उनके पति गोरेलाल प्रजापति आग की लपटों से घिरे घर से बाहर निकलकर किसी तरह जान बचाने में सफल रहे. हालांकि वे भी आग से झुलस गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय वृद्ध दंपती घर के अंदर सो रहे थे. थाना प्रभारी गुनौर माधवी अग्निहोत्री ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए कमरे के भीतर आग जलाई थी.

बंगाल में मतदाताओं का नाम हटा रहा चुनाव आयोग- तृणमूल

नई दिल्ली, 06 फरवरी. तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने का आरोप लगाया और कहा कि ये नाम चुनाव निकाय द्वारा इस्तेमाल किए गए एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर के जरिये हटाए गए हैं.

तृणमूस कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि अब तो आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सही वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गये. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कई महीनों से इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा-आखिरकार आयोग के अधिकारियों ने भी मान लिया है कि बंगाल की मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम एक रहस्यमय खराब सॉफ्टवेयर के कारण हटाए गए हैं. उन्होंने कहा हमारे नेताओं ने महीनों से इस ओर इशारा किया है और फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुप रहे हैं. कथित सॉफ्टवेयर पर सवाल उठाते हुए श्री गोखले ने कहा कि यह प्रणाली किसने बनायी और खराब होने के बावजूद इसका इस्तेमाल क्यों किया गया. उन्होंने कहा, आयोग के लिए यह रहस्यमय सॉफ्टवेयर किसने बनाया जो सही वोटरों के नाम हटा देता है? आयोग यह जानते हुए भी कि यह खराब है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं रोक रहा है?

चुराचांदपुर में शपथ ग्रहण विरोध पर हिंसा

मणिपुर,06 फरवरी. चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को हिंसा भड़क गई, जब नए उपमुख्यमंत्रियों नेम्चा किप्गेन और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया. तुइबोंग मेन मार्केट में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों को वापस बैरक में भेजने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कुछ लोगों ने सड़क पर टायर भी जला दिए. आदिवासी संगठन जॉइंट फोरम ऑफ सेवन ने चुराचांदपुर में शुक्रवार सुबह 6 से 12 घंटे का बंद बुलाया है. वहीं, कुछ संगठनों ने नेम्चा किप्गेन को मारने वाले को 20 लाख और विधायकों एलएम खाउते व एन सेनाते को मारने वाले को 10-10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है.

डिएगो गार्सिया बेस को सुरक्षित करना अमेरिका का अधिकार : ट्रंप

वाशिंगटन, 06 फरवरी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर सख्त रुख अपनाया है.

उन्होंने कहा कि वह इस बेस को कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे और अगर भविष्य में कोई लीज समझौता टूटता है या अमेरिकी सेना को खतरा होता है तो वे इसे 'मिलिट्री तरीके से सुरक्षित और मजबूत' करने का अधिकार रखते हैं. ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से इस मामले पर बातचीत की और इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया.

ट्रंप ने कहा कि डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित है और अमेरिकी सैन्य

ऑपरेशनों की सफलता में इसके बेस की भूमिका अहम रही है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह के 'झूठे दावे' या पर्यावरण के नाम पर इसे कमजोर नहीं होने देंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ट्रंप के बयान को दोहराते हुए कहा कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकार बरकरार हैं और जरूरत पड़ने पर अमेरिका दुनिया में कहीं भी अपनी संपत्ति की रक्षा करेगा.

सरकारें हादसों से कोई सबक नहीं ले रही

नोएडा हादसे को लेकर अरविंद केजरीवाल का तंज

नई दिल्ली, 06 फरवरी. नोएडा में हुई दर्दनाक घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है.

उन्होंने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए सरकार की लापरवाही का नतीजा बताया है. केजरीवाल का यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. अपने पोस्ट में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि

सरकारें बीते हादसों से कोई सबक नहीं ले रहीं और गैर-जिम्मेदार रवैया अब उनकी पहचान बन चुका है. उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाहियों का खामियाजा आम जनता, खासकर मासूमों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उन्हें शक्ति देने की प्रार्थना भी की.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नोएडा की इस घटना ने एक बार फिर सरकारी जिम्मेदारी और जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है. नोएडा में हुई एक दर्दनाक घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने बयान में केजरीवाल ने इस घटना को हादसा मानने से इनकार करते हुए इसे सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया. केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, ये हादसा नहीं, बल्कि हत्या है.

एक नजर में

वर्ल्ड डिफेंस शो : भारत की रक्षा ताकत का प्रदर्शन

नईदिल्ली, 06 फरवरी. सऊदी अरब में 8-9 फरवरी को आयोजित होने जा रहे 'वर्ल्ड डिफेन्स शो 2026' में भारत भी प्रमुख रूप से भाग लेगा. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस बार 700 से अधिक रक्षा कंपनियां और लगभग 400 सरकारी व आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे. भारत पहली बार इस शो में अपना 'इंडिया पवेलियन' लगाएगा, जिसका उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री करेंगे. 400 वर्ग मीटर में फैले पवेलियन में भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और उत्पादन क्षमता प्रदर्शित की जाएगी.

इटावा हाईवे टोल का मामला गडकरी तक पहुंचा

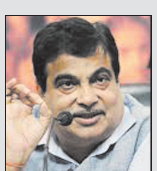

इटावा, 6 फरवरी. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बख्तियारपुरा टोल प्लाजा पर शुरू की गई वसूली के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र कुमार दोहरे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. सांसद ने पत्र में टोल वसूली को नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल बंद कराने का अनुरोध किया है.

मंत्रालय ने लाइटवेट रडार खरीदने प्रस्ताव मांगे

नई दिल्ली 06 फरवरी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तान के ड्रोनों के भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ करने के बाद सीमाओं पर निगरानी को पुख्ता करने के लिए सेना 725 करोड़ रुपये की लागत से 30 अत्याधुनिक रडार लाइटवेट रडार खरीदने जा रही है. रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 30 लाइटवेट राडार की खरीद के लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगे है. यह खरीद फास्ट ट्रैक खरीद प्रक्रिया से की जायेगी. ये नये राडार कम ऊंचाई पर उडने वाले ड्रोन का पता लगाने में सक्षम हैं. इन प्रस्तावों के संबंध में सेना की वेबसाइट पर जानकारी दी गयी है. इस खरीद सौदे की आरएफपी के अनुसार खरीद में न्यूनतम 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री अनिवार्य की गई है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है.

विस अध्यक्ष को अवमानना की चेतावनी

दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

नई दिल्ली, 06 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वे भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी शेष अयोग्यता याचिकाओं पर तीन सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से निर्णय लें.

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही शुरू की जायेगी. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ शुक्रवार को 31 जुलाई 2025

के अपने उस आदेश के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी, जिसके तहत अध्यक्ष को कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय दिया था. अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अवधि में निर्णय न लेने के कारण न्यायालय में अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि दिसंबर 2025 में सात याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था.

आईपीएस मीणा के दावे को किया खारिज

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उसी चयन वर्ष के लिए राजस्थान कैडर में एक आंतरिक रिक्ति के आवंटन की मांग की थी. अदालत ने कहा कि इस तरह के विलंबित दावों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कैडर आवंटन की व्यवस्था को अस्थिर कर देंगे. न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने टिप्पणी की कि अपीलकर्ता रूपेश मीणा ने 2004 के चयन के छह साल बाद केवल 2010 में अपना दावा पेश किया था.

श्रमिकों की समृद्धि से ही होती है देश की प्रगति- डॉ. मांडविया

नई दिल्ली, 06 फरवरी. श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि श्रमिकों की समृद्धि से देश की प्रगति होती है इसलिए श्रमिकों का कल्याण, सम्मान और सुरक्षा राष्ट्रीय विकास के प्रति सरकार की दृष्टि का केंद्र बिंदु है.

डॉ. मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा कि ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ के 21वें त्रैवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. उनका कहना था कि श्रम राष्ट्र निर्माण का आधार है और श्रमिकों का सम्मान विकसित भारत की दिशा तय करता है और प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे इस संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग दे रहे हैं. उनका कहना था कि न केवल देश का सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसने श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने, देश के कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आज का इतिहास

- 1792 – आस्ट्रेलिया एवं एशिया ने फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 1831 – बेल्जियम में संविधान लागू।
- 1856 – नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलयन।
- 1898 – रमाबाई अंबेडकर का जन्म, वह डॉ. भीमराव अंबेडकर की पत्नी थीं।
- 1904 – अमेरिका के बाल्टिमोर में जबरदस्त आग लगने से पन्द्रह सौ इमारतें जल कर खाक।

पोलैंड : भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर

नई दिल्ली,06 फरवरी. पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की ने कहा है कि भारत अब एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया में चौथे स्थान पर है और 1.5 अरब लोगों के विशाल बाजार को कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता. भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (स्त्रङ्ग) होना बेहतर है, क्योंकि टैरिफ से आम लोगों पर लागत बढ़ती है. कम शुल्क से समृद्धि बढ़ती है. व्यापारिक संबंधों में पोलैंड ने आईसीटी सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की बात कही, क्योंकि यह भारत की

जीडीपी का लगभग 9 प्रतिशत और पोलैंड की 7 प्रतिशत है. साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस में भी सहयोग की संभावनाएं हैं. बार्टोशेव्स्की ने सैन्य तकनीक में संयुक्त उत्पादन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पोलैंड भारत के साथ कोयला खनन पर भी बातचीत करने की योजना बना रहा है.

कृत्रिम सूर्य में प्लाज्मा प्रवाह बनाने रचा इतिहास

चीन के शंघाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का दावा

शंघाई, 06 फरवरी. चीन के शंघाई शहर में स्थित स्टार्टअप एनर्जी सिंगुलैरिटी ने घोषणा की है कि उसके एचएच 70 उच्च तापमान सुपरकंडक्टिंग (एचटीएस) टोकामक (कृत्रिम सूर्य) ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

इस नाभिकीय संलयन उपकरण ने 1,337 सेकंड तक निरंतर, लंबी अवधि के प्लाज्मा प्रवाह को बनाए रखने में सफलता हासिल की है. सूर्य की नकल करने वाले परमाणु संलयन यंत्र को हमारी उर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन उत्सर्जन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक प्रमुख

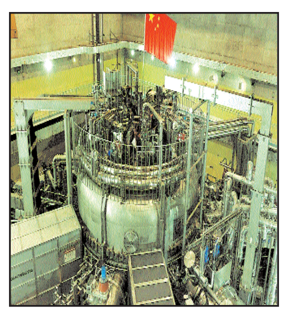

उपकरण के तौर पर देखा जाता है. चीन की पहली निजी संलयन ऊर्जा कंपनी के रूप में 2021 में स्थापित एनर्जी सिंगुलैरिटी ने जून 2024 में दुनिया के पहले एचटीएस टोकामक एचएच70 का निर्माण और संचालन पूरा किया था. इस उपकरण ने अब तक 5,755 प्रयोग किए हैं, जिसमें नवीनतम दौर ने हजार-सेकंड से अधिक तक उर्जा के स्थिर प्रवाह को प्राप्त किया है.

उल्लेखनीय है कि टोकामक से स्थाई उर्जा या बिजली प्राप्त करना तभी संभव है जब प्लाज्मा का प्रवाह लगातार स्थिर बना रहे. कंपनी के अनुसार, यह उपलब्धि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित प्लाज्मा नियंत्रण प्रणाली के निरंतर अनुकूलन से संभव हुई है. एनर्जी सिंगुलैरिटी के सह-संस्थापक डोंग गे ने कहा, यह सफलता केवल समय के बारे में नहीं है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दर्शाती है कि एचटीएस और एआई नियंत्रण प्रौद्योगिकियों का गहरा एकीकरण इंजीनियरिंग स्तर पर व्यवहार्य हो गया है. यह भविष्य के संलयन बिजली संयंत्रों के कम लागत और उच्च दक्षता वाले निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है.

पुलिस ने पांच नाबालिगों सहित 11 लड़कियों को कराया मुक्त

नई दिल्ली. दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की पुलिस ने द्वारका में एक वेश्यावृत्ति के अड्डे पर छापा मारकर 11 युवतियों को मुक्त कराया जिनमें पांच नाबालिग बच्चियां हैं. पुलिस के अनुसार एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन से मिली पुख्ता जानकारियों के बाद सदस्यों ने फर्जी ग्राहक बन इस इस गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई. इन लड़कियों को बेहतर अवसरों और नौकरी का झांसा देकर ट्रैफिकिंग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश से लाया गया था. पुलिस ने छापे में आठ ग्राहकों और मौके से दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया. जिनके इस अड्डे का संचालक होने का शक है. इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

इंडो-यूएस ट्रेड डील **कृषि और डेयरी पर कोई समझौता नहीं**

डील पर बहस से भाग रहा विपक्ष : शिवराज सिंह

नई दिल्ली, 6 फरवरी. भारत-यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भ्रामक आरोपों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारतीय कृषि, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का नया उदाहरण है और

प्रधानमंत्री जी ने शुरू से साफ कर दिया था कि किसान हित सर्वोपरि हैं. दिल्ली में आज मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे मुख्य अनाज, फल, प्रमुख फसलें, मिलेट्स और डेयरी उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और भारतीय कृषि या डेयरी पर किसी तरह का खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित पूरी तरह संरक्षित हैं और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे. छोटे किसानों की चिंता और यूएस फार्म प्रोडक्ट्स पर स्थिति स्पष्ट इस आशंका पर कि देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, छोटे किसानों पर असर पड़ सकता है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोई बड़ी चीज भारत के बाजार में अचानक नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि हमारी सभी मुख्य फसलें, मुख्य अनाज, फल और डेयरी उत्पाद सुरक्षित है.

सिंह ने बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका सहित विभिन्न देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है और हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 63,000 करोड़ रुपये के चावल का निर्यात किया था. टैरिफ कम होने से हमारे चावल, मसालों और टेक्सटाइल के निर्यात को बल मिलेगा और जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ कपास उगाने वाले हमारे किसानों को होगा. श्री चौहान ने कहा कि यह समझौता समग्र रूप से भारत के किसानों के हित में है.

गडढे में गिरकर युवक की मौत, तीन सस्पेंड

नई दिल्ली ,06 फरवरी. पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी में 15 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. यह घटना 5 फरवरी की देर रात हुई, जब 25 वर्षीय कमल भयानी दिल्ली जल बोर्ड की निर्माण साइट पर खोदे गए गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. कमल कैलाशपुरी का निवासी था और एक प्राइवेट बैंक के कॉल सेंटर में कार्य करता था. घटना की सूचना मिलने पर 6 फरवरी सुबह 8 बजे पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और गड्ढे से कमल का शव निकाला.

भरोसेमंद सेवा देना भारत टैक्सी का लक्ष्य

नईदिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा

नई दिल्ली, 06 फरवरी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य दिल्ली आने वाले पर्यटकों के साथ ही यहां के नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद, पारदर्शी टैक्सी सेवाएं देना, टैक्सी चालकों की आय एवं सम्मान को मजबूत करना है.

श्रीमती गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने भारत टैक्सी के सहकारी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ औपचारिक साझेदारी की है. इसका उद्देश्य दिल्ली आने वाले पर्यटकों और यहां के नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और पारदर्शी टैक्सी

सेवाएं देना तथा टैक्सी चालकों की आय एवं सम्मान को मजबूत करना है. यह समझौता एक साथ ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवल और ईज ऑफ अर्निंग को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने भारत टैक्सी की सहकारी इकाई सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य दिल्ली में सहकारी मॉडल के तहत आधुनिक और भरोसेमंद टैक्सी सेवाओं को मजबूत करना है. परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसे मॉडल को आगे बढ़ाना है, जिसमें तकनीक के साथ-साथ मानवीय गरिमा और आजीविका की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो. सहकारी टैक्सी मॉडल इसी सोच को जमीन पर उतारता है. उन्होंने बताया कि इस साझेदारी के तहत डीटीटीडीसी पर्यटन और ब्रांडिंग पार्टनर की भूमिका निभाएगा.